

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक: एफ 11-37/सूअप्र/05/1-9

भोपाल, दिनांक: 03/04/2008

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागायुक्त,
5. समस्त कलेक्टर,
6. समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषय म0प्र0सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 में संशोधन के संबंध में ।
संदर्भ: विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.10.2005 एवं 28 अक्टूबर, 05.

—000—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा म0प्र0राज्य सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2008 द्वारा किये गये संशोधन की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है ।

2- निर्देशानुसार अनुरोध है कि इस संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार.

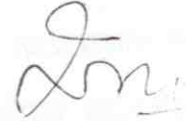
(एस0सी0पाराशर)
अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवाल, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
6. रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर।
7. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवाल, भोपाल।
8. सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्य प्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
10. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश भोपाल।
12. सचिव, राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
13. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण / अभिलेख मंत्रालय भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 मार्च 2008—फाल्गुन 27, शक 1929

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2008

क्र. एफ-11-37-05-एक-9.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 5 में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द “तीन दिवस” के स्थान पर, शब्द “पन्द्रह कार्य दिवस” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किये जाएं; अर्थात्:—

“(5) गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक द्वारा इस अधिनियम के अधीन चाही गई सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात् :-

(एक) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध है, तब सूचना ऐसे प्ररूप में, जिसमें वह मांगी गई है, उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते सूचना उस प्ररूप में उपलब्ध हो, तथा प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा के लिये अहितकर न हो सकेगी;

(दो) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध नहीं है, किन्तु सूचना पचास पृष्ठों (ए-4 साइज के) तक सीमित है, तब चाही गई सूचना की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी बशर्ते की वह प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा के लिए अहितकर न हो;

- (तीन) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध नहीं है तथा सूचना पचास पृष्ठों (ए-4 साइज के) से अधिक की है, तब अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, आवेदक से कार्यालय में अभिलेख नस्ती का निरीक्षण करने के लिए कहा जायेगा तथा सूचना को सीमित करने के लिए अनुरोध किया जायेगा.
- (6) यदि आवेदक, विभागों द्वारा प्रकाशित की गई मुद्रित रिपोर्ट तथा अन्य सामग्री चाहता है, तो वह ऐसे प्रकाशनों के लिए नियत कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकेगी. नियम 5 के उपनियम (1) में नियत की गई दरों के अनुसार ऐसे प्रकाशनों से उद्धरण उपलब्ध कराये जा सकेंगे.
- (7) यदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदक, ऐसी सूचना मांगता है, जहां किसी अन्य अधिनियम/नियम में ऐसी सूचना के लिए पृथक् फीस का उपबंध है, वहां आवेदक को तत्स्थानी अधिनियम/नियम के अधीन यथा-उपबंधित ऐसी फीस का भुगतान करना होगा.".
2. नियम, 7 के उपनियम (2) में, शब्द "सक्षम अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "लोक सूचना अधिकारी" स्थापित किए जाएं.
3. नियम 8 में,—
- (एक) उपनियम (3) में शब्द "30 दिवस" के स्थान पर, शब्द "एक सौ अस्सी दिवस" स्थापित किए जाएं;
- (दो) उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
- "(6) शास्ति की रकम की वसूली हेतु प्रक्रिया :—
- (एक) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी किए गए शास्ति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर अधिरोपित शास्ति नकद या बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के रूप में राज्य सूचना आयोग के पास जमा करेगा;
- (दो) राज्य सूचना आयोग को शास्ति की वसूली के लिए धारा 18 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो कि सिविल न्यायालय में निहित हैं. सूचना आयोग, शास्ति की वसूली के लिए पृथक् मामला रजिस्ट्रारित करके इस शक्ति के अधीन कार्यवाही आरंभ करेगा;
- (तीन) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी विहित समय-सीमा के भीतर अधिरोपित शास्ति की रकम जमा करने में असफल रहता है तो राज्य सूचना आयोग संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को, राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए तथा अधिरोपित शास्ति की रकम की वसूली के लिए रिपोर्ट करेगा. ऐसे मामलों में राज्य सूचना आयोग का आदेश संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी होगा;
- (चार) यदि अधिरोपित शास्ति की रकम राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के वेतन से वसूल नहीं की जाती है तो उसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर उससे वसूल किया जाएगा.".
4. नियम 3 के उपनियम (1) तथा (2), नियम 4, नियम 5 के उपनियम (1), (2), (3) तथा (4) तथा नियम 7 के उपनियम (1) और नियम 8 के उपनियम (2) में, शब्द "नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प" के पश्चात् शब्द "खजाना चालान की मूलप्रति" अंतःस्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. अग्रवाल, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2008

क्र. एफ-11-37-05-सूअप्र-एक-9.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. अग्रवाल, सचिव।

Bhopal, the 10th March 2008

No. F 11-37-2005-I-9.— In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Right to Information (Fees and Appeal) Rules, 2005, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Rule 5,—

- (i) In sub-rule (1), for the words “three days”, the words “fifteen working days” shall be substituted;
- (ii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(5) The Information sought by the applicant below poverty line under this Act shall be provided as under,—

- (i) if the Information sought is directly related with the applicant, then the Information shall be provided in the form, in which it is demanded, provided the Information is available in that form and would not be detrimental to the safety of the record in question;
- (ii) if the Information sought is not directly related with the applicant, but the Information is limited up to fifty pages (of A-4 size), then the photo copies of the Information sought shall be made available, provided that it would not be detrimental to the safety of the record in question;
- (iii) if the Information sought is not directly related with the applicant, and the Information is of more than fifty pages (of A-4 size), then after recording reasons under sub-section (9) of Section 7 of the Act, the applicant shall be asked to inspect the record file in the office and shall be requested to limit the Information.
- (6) if the applicant wants printed reports and other materials published by the departments, they can be provided at the price fixed for such publications. Extracts from such publications can be provided as per rates fixed in sub-rule (1) of Rule 5.
- (7) if under Right to Information Act, 2005 the applicant asks for such Information, where some other Act/Rules provides for separate fee for such Information, then the applicant has to pay such fees as provided under the corresponding Act/Rule.

2. In sub-rule (2) of Rule 7, for the words “Competent Officer”, the words “Public Information Officer” shall be substituted.

3. In Rule 8,—

(i) in sub-rule (3), for the words "Thirty days" the words "one hundred eighty days" shall be substituted.

(ii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) Process for recovery of Penalty amount:—

(i) the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer shall deposit the imposed penalty in cash or in the form of bank draft or banker's cheque, with the State Information Commission within one month from the date of receipt of penalty order issued by the State Information Commission.

(ii) for recovery of penalty the State Information Commission under clause (f) of sub-section (3) of section 18 shall have the same powers, as are vested in a Civil Court. The Information Commission shall initiate the action under this power, by registering a separate case for recovery of penalty;

(iii) if the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer fails to deposit the imposed penalty amount within the prescribed time limit, then the State Information Commission shall report to concerned disciplinary authority for taking disciplinary action and for recovery of imposed penalty amount against the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer. In such cases, the order of the State Information Commission shall be binding on the concerned officer.

(iv) if the imposed penalty amount is not recovered from the salary of the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer, then the same shall be recovered from him as arrears of land revenue."

4. In sub-rule (1) and (2) of rule, 3, rule 4, sub-rule (1), (2), (3) and (4) rule 5 and sub-rule (1) of rule 7 and sub-rule (2) of rule 8, after the words "non-judicial stamp", the words "original copy of Treasury Challan" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. AGRAWAL, Secy.